Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to constitute Joint Education Council for implementing new education policy in Himalayan States.

श्री किशन कपूर (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने गत जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। यह शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैले हुए विशाल हिमालयी राज्यों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हिमालयी राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी है। हिमालयी राज्यों के दूर-दराज के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अध्यापकों और स्कूलों तक डिजिटल टेक्नोलॉज़ी की पहुंच का अभाव है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने का संकल्प भी वर्तमान स्थिति में पूरा होने की संभावनाएं क्षीण हैं। पहाड़ी राज्यों में एक कहावत प्रचलित है कि कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। मेरे राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए तो यह अक्षरशः सत्य बैठता है। मेरे राज्य में 12 जिले हैं। इन 12 जिलों में 14 बोलियां बोली जाती हैं, जो कि राज्य अधिकृत रूप से केवल हिन्दी और अंग्रेजी पर आश्रित हैं। वहां मातृभाषा में पढ़ाना तब तक संभव नहीं है, जब तक पहाड़ी भाषाओं पर शोध कर उन्हें पढ़ाए जाने योग्य बनाया न जा सके। जैसा कि शिक्षा नीति में वर्णित है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि हिमालयी राज्यों के लिए एनसीआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित की जाए, ताकि इन राज्यों में नई शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू की जा सके और मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम आदि की समस्या पर विचार किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री कुलदीप राय शर्मा और

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री किशन कपूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।